राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई–नाम) प्लेटफॉर्म– संचालन, लाभ और चुनौतियाँ

सेतु रत्नम
कृषि विभाग, इंटीग्रल कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिक संस्थान, इंटीग्रल विश्वविद्यालय, लखनऊ–226 026, उ.प्र., भारत
ईमेलः seturatnam@iul.ac.in

ई–नाम, या राष्ट्रीय कृषि बाजार, भारत में एक पैन–इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो मौजूदा कृषि उपज विपणन समिति और अन्य बाजार यार्डों को जोड़कर कृषि उत्पादों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने का प्रयास करता है। यह एक ''आभासी'' बाजार है, लेकिन इसके पीछे एक भौतिक बाजार (मंडी) है। ई–नाम का उद्देश्य किसानों को अपने उत्पादों की बिक्री के लिए अधिक विकल्प और बेहतर मूल्य प्रदान करना है, जिससे व्यापार की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाया जा सके। इसके माध्यम से, व्यापारी किसी भी राज्य से ऑनलाइन बोली लगा सकते हैं, जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और किसानों को उनके उत्पाद के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त होता है। ई–नाम का संचालन भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है और इसे छोटे किसानों के कृषि व्यवसाय संघ के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है।

परिचय

ई–नाम को एक पैन–इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल के रूप में परिकल्पित किया गया है, जो मौजूदा कृषि उपज विपणन समिति और अन्य बाजार यार्डों को जोड़कर कृषि उत्पादों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने का प्रयास करता है। ई–नाम एक ''वर्चुअल'' बाजार है, लेकिन इसके पीछे एक भौतिक बाजार (मंडी) है। ई–नाम एक समानांतर विपणन संरचना नहीं है, बल्कि यह भौतिक मंडियों के एक राष्ट्रीय नेटवर्क को ऑनलाइन पहुंच प्रदान करने के लिए एक उपकरण है। यह मंडियों के भौतिक बुनियादी ढांचे का उपयोग करके एक ऑनलाइन ट्रेडिंग पोर्टल के माध्यम से क्रेताओं को राज्य के बाहर बैठकर भी स्थानीय स्तर पर व्यापार में भाग लेने में सक्षम बनाता है। कृषि उत्पादों के लिए एक सामान्य राष्ट्रीय बाजार के उद्भव को सुविधाजनक बनाने के लिए ई–नाम की आवश्यकता है। वर्तमान कृषि उपज विपणन समिति विनियमित बाजार कृषि उत्पादों पर व्यापार की सीमाएं (फसल के बाद उत्पाद) स्थानीय बाजार में, आमतौर पर तालुका / तहसील या अधिकतम जिला स्तर पर, रखती हैं। एक राज्य भी एक एकीकृत कृषि बाजार नहीं है और एक ही राज्य के भीतर एक बाजार क्षेत्र से दूसरे बाजार क्षेत्र में उत्पाद को स्थानांतरित करने पर लेन–देन लागत होती है। विभिन्न बाजार क्षेत्रों में व्यापार करने के लिए कई लाइसेंस आवश्यक होते हैं। इन सभी ने एक अत्यधिक विखंडित और उच्च लागत वाली कृषि अर्थव्यवस्था को जन्म दिया है, जो पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं और कृषि वस्तुओं की निर्बाध आवाजाही को रोकती है। ई–नाम इस विखंडन प्रक्रिया को संवर्धित करने और इसे बदलने का प्रयास करता है, अंततः मध्यस्थता लागत, बर्बादी और अंतिम उपभोक्ता के लिए कीमतों को कम करता है।

ई–नाम इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का निर्माण भारत सरकार (कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के माध्यम से) द्वारा निवेश के साथ किया गया है। यह किसी भी राज्य में मौजूदा बाजार (चाहे वह विनियमित हो या निजी) को ''प्लग–इन'' की सुविधा प्रदान करता है। ई–नाम के लिए विकसित विशेष सॉफ्टवेयर प्रत्येक मंडी को राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने के लिए आवश्यक अनुकूलन के साथ निःशुल्क उपलब्ध है ताकि यह प्रत्येक राज्य मंडी अधिनियम के विनियमों का पालन कर सके। जो राज्य अपनी मंडियों को ई–नाम के साथ एकीकृत करने में रुचि रखते हैं, उन्हें अपने कृषि उपज विपणन समितिअधिनियम में निम्नलिखित सुधार करने होंगेः

- इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के लिए विशिष्ट प्रावधान।
- राज्य की सभी मंडियों में व्यापार के लिए एकल व्यापार लाइसेंस।
- लेनदेन शुल्क का एकल बिंदु लेवी।

राष्ट्रीय कृषि बाजार

ई–नाम मूल रूप से किसान के विकल्प को बढ़ाता है जब वह बिक्री के लिए मंडी में अपना उत्पाद लाता है। स्थानीय व्यापारी उत्पाद के लिए बोली लगा सकते हैं, जैसे कि अन्य राज्यों में बैठे व्यापारी भी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर बोली लगा सकते हैं। किसान स्थानीय विकल्प या ऑनलाइन विकल्प में से किसी एक को स्वीकार करने का विकल्प चुन सकता है। किसी भी मामले में, लेनदेन स्थानीय मंडी की पुस्तकों पर होगा और वे लेनदेन शुल्क अर्जित करना जारी रखेंगे। वास्तव में, विशिष्ट उत्पाद के लिए अधिक प्रतिस्पर्धा के कारण व्यापार की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिससे मंडी के लिए उच्च लेनदेन शुल्क प्राप्त होगा।

राष्ट्रीय स्तर का प्लेटफॉर्म कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है, जो रखरखाव लागत भी वहन करेगा। जैसा कि ऊपर कहा गया है, स्थानीय मंडियों के लिए एकीकरण लागत और सॉफ्टवेयर का अनुकूलन, प्रशिक्षण आदि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एक बार की अनुदान राशि के रूप में भुगतान किया जाएगा। इसके बाद, स्थानीय स्तर पर सॉफ्टवेयर की चल रही लागत, गुणवत्ता जांच के लिए कर्मचारियों की लागत आदि उत्पाद की बिक्री के माध्यम से उत्पन्न लेनदेन शुल्क से पूरी की जाएगी। उद्देश्य यह है कि मंडी के ई–नाम में एकीकृत होने पर कोई अग्रिम निवेश न हो, और अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करके चल रही लागत का समर्थन करने में सक्षम हो।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई–नाम) प्लेटफॉर्म में इसे और अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल बनाने के लिए छह नई विशेषताएँ जोड़ी हैं। इसमें बेहतर विश्लेषण के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली डैशबोर्ड, व्यापारियों द्वारा भीम (भीम / भारत इंटरफेस फॉर मनी) भुगतान सुविधा, व्यापारियों द्वारा मोबाइल भुगतान सुविधा, गेट एंट्री और भुगतान जैसी मोबाइल ऐप पर बढ़ी हुई सुविधाएँ, किसानों के डेटाबेस का एकीकरण और ई–नाम वेबसाइट में ई–लर्निंग मॉड्यूल शामिल हैं। व्यापार के दौरान, व्यापारियों को मोबाइल ऐप पर परीक्षण प्रमाणपत्र देखने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अब, ई–नाम मोबाइल ऐप से डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से व्यापारी (खरीदार) द्वारा ऑनलाइन भुगतान भी किया जा सकता है। यह खरीदारों को सीधे ऐप के माध्यम से भुगतान स्थानांतरित करने में मदद करेगा और किसानों को ऑनलाइन भुगतान करने में व्यापारियों को आसान बनाएगा। साथ ही, बैंक खाते में भुगतान प्राप्त करने पर किसान को एसएमएस अलर्ट भेजा जाएगा जिससे किसानों को भुगतान प्राप्ति की जानकारी मिलेगी।

वर्तमान में, ई–नाम पोर्टल आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी., डेबिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से किसानों को सीधे ऑनलाइन भुगतान की सुविधा प्रदान करता है। भीम के माध्यम से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यू.पी.आई.) की सुविधा किसानों को भुगतान को सरल बनाने में एक और मील का पत्थर है जिससे खरीदार के खाते से पूल खाते में भुगतान के समय को कम किया जा सकेगा और बदले में किसानों को वितरण किया जा सकेगा। इसके अलावा, एक नई वेबसाइट विकसित की गई है जिसमें प्रवेश द्वार के आधार पर ई–नाम बाजारों की लाइव स्थिति, घटनाओं पर नवीनतम जानकारी, गतिशील प्रशिक्षण तिथि–पत्रिका आदि जैसी बेहतर और अधिक जानकारीपूर्ण विशेषताएँ हैं। साथ ही, हिंदी भाषा में ई–लर्निंग मॉड्यूल को वेबसाइट में डिजाइन और शामिल किया गया है ताकि विभिन्न हितधारक प्रणाली को संचालित करने के तरीके के बारे में ऑनलाइन सीख सकें और अपनी सुविधा पर प्रणालीपर निरंतर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। व्यापारिक बुद्धिमत्ता पर आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली डैशमंडल प्रत्येक मंडी के आगमन और व्यापार के मामले में अधिक अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। यह मंडी मंडल अधिकारियों और कृषि उपज विपणन समिति सचिव को दैनिक, साप्ताहिक, मासिकध्त्रैमासिक और वर्ष–दर–वर्ष के आधार पर प्रत्येक मंडी के प्रदर्शन की तुलना करने में मदद करेगा। यह अधिकारियों और मंडी सचिव को वस्तु स्तर से राज्य स्तर के संचालन तक वास्तविक व्यापार विश्लेषण करने में सक्षम करेगा। यह मंडी मंडल और मंडी सचिव के लिए ऐतिहासिक विश्लेषण के बाद उनके संचालन की योजना बनाने और समन्वय करने में भी फायदेमंद होगा।

साथ ही, ई–नाम को केंद्रीय किसान डेटाबेस के साथ एकीकृत किया गया है ताकि पंजीकरण प्रक्रिया आसान हो सके और मंडी गेट पर आगमन पर किसानों की पहचान आसानी से की जा सके जिससे दक्षता बढ़ेगी और समय कम होगा। यह रबी और खरीफ के चरम समय के दौरान गेट पर लोड को अधिक कुशलता से प्रबंधित करने में मदद करेगा और प्रवेश गेट पर किसानों के प्रतीक्षा समय को कम करेगा"।

ई–नाम वेबसाइट अब आठ विभिन्न भाषाओं (हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, बंगाली और उड़िया) में उपलब्ध है जबकि लाइव ट्रेडिंग सुविधा छह विभिन्न भाषाओं (हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, गुजराती, मराठी और तेलुगु) में उपलब्ध है।

ई–नाम प्लेटफॉर्म का संचालन

भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई–नाम) के प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में छोटे किसानों के कृषि व्यवसाय संघ को नियुक्त किया है। छोटे किसानों के कृषि व्यवसाय संघ, रणनीतिक साझेदार की मदद से ई–नाम प्लेटफॉर्म का संचालन और रखरखाव करेगा, जिसे इस उद्देश्य के लिए चुना गया है।

ई–नाम के कार्यान्वयन में भाग लेने वाली विभिन्न एजेंसियाँ

- छोटे किसानों के कृषि व्यवसाय संघः यह रणनीतिक साझेदार (एस.पी.) के तकनीकी समर्थन के साथ ई–नाम का संचालन कर रहा है।
- विपणन और निरीक्षण निदेशालय
- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र
- रणनीतिक साझेदार
- राज्य सरकारें/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन
- राज्य कृषि विपणन मंडल/कृषि विपणन निदेशालय
- कृषि उत्पाद विपणन समिति/विनियमित बाजार समिति

ई–नाम से लाभ

- *हितधारकों के लिए बेहतर समाधान* : ई–नाम सभी हितधारकों के लिए एक बेहतर समाधान के रूप में परिकल्पित है।
- *किसानों के लिए अधिक विकल्प* : ई–नाम निकटतम मंडी में बिक्री के अधिक विकल्प प्रदान करता है।
- *स्थानीय व्यापारियों के लिए अवसर* : ई–नाम स्थानीय मंडी में व्यापारियों के लिए द्वितीयक व्यापार के लिए एक बड़े राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच का अवसर प्रदान करता है।
- *बड़े खरीदारों के लिए लाभ* : बड़े खरीदार, प्रसंस्करण, निर्यातक आदि ई–नाम प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीधे स्थानीय मंडी स्तर पर व्यापार में भाग लेकर अपने मध्यस्थता लागत को कम कर सकते हैं।
- *राज्य मंडियों का एकीकरण* : राज्यों में सभी प्रमुख मंडियों का ई–नाम में क्रमिक एकीकरण लाइसेंस जारी करने, शुल्क लगाने और उत्पाद की आवाजाही के लिए सामान्य प्रक्रियाएं सुनिश्चित करेगा।
- *लाभ* : निकट भविष्य में, हम किसानों के लिए उच्च लाभ, खरीदारों के लिए कम लेन–देन लागत और उपभोक्ताओं के लिए स्थिर कीमतों और उपलब्धता के माध्यम से महत्वपूर्ण लाभ की उम्मीद कर सकते हैं।
- *मूल्य श्रृंखला का एकीकरण* : ई–नाम प्रमुख कृषि वस्तुओं में एकीकृत मूल्य श्रृंखलाओं के उभरने को भी सुविधाजनक बनाएगा और कृषि वस्तुओं के वैज्ञानिक भंडारण और आवाजाही को बढ़ावा देने में मदद करेगा।

ई–नाम के क्रियान्वयन में प्रमुख बाधाऐं

- *गुणवत्ता और मानकों में असमानता* : ई–नाम की सफलता के लिए विभिन्न बाजारों में परीक्षण सुविधाएं आवश्यक हैं ताकि गुणवत्ता के गुणों का निर्धारण किया जा सके। राज्य भर में गुणवत्ता

मानकों के सामंजस्य के लिए गुणवत्ता परीक्षण (अस्सायिंग) बुनियादी ढांचे का प्रावधान और गुणवत्ता मानकों को बाजार प्रतिभागियों के साथ संप्रेषण की आवश्यकता है।

- *मूल्य श्रृंखला का समन्वय* : मूल्य श्रृंखला गतिविधियों को परतवार प्रक्रिया में समन्वयित करने के लिए प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है। ई–नाम को एक विपणन प्रणाली के रूप में देखा जाता है जो कृषि उत्पादों की उत्पादन–पश्चात आपूर्ति श्रृंखला को सुगम बनाएगा। मूल्य श्रृंखला प्रणाली का एकीकरण अनुसंधान, विकास, प्रथम पंक्ति प्रदर्शन, विस्तार कार्य, बाजार सूचना जैसी द्वितीयक गतिविधियों को भी शामिल करता है।
- *बाजार प्रतिभागियों का एकीकृत विकास* : ई–नाम को किसानों के उत्पाद बेचने के लिए संलग्नता की आवश्यकता होती है। किसान उत्पादक संगठनों को संगठनात्मक कौशल, टीम में काम करने, व्यक्तिगत संचार, कार्य आवंटन, ऑनलाइन भुगतान और लेन–देन, प्रतिज्ञा वित्त आदि पर मजबूत करने की आवश्यकता है।
- *बाजार एजेंसियों और बाजार सेवाओं का समन्वय* : नेटवर्क संगठन और बाजार एजेंसियों जैसे गोदाम और प्रबंधन एजेंसियाँ, वित्तीय संस्थान, आपूर्ति श्रृंखला प्रदाता प्रशिक्षण और विस्तार संगठनों के समन्वय की आवश्यकता है। डिजिटल चरण की ओर बाजारों के रूपांतरण के रूप में, विविध और असमान समूहों की ग्राहक, सार्वजनिक और निजी संगठन को अनुकूलित सेवाएं प्रदान करने के लिए एकीकृत किया जाना चाहिए।
- *ग्रामीण बाजारों का एकाधिकार* : भारत के कुछ राज्यों में पंचायती बाजारों और कृषि उपज विपणन समितिके बीच व्यावसायिक संचालन को लेकर संघर्ष होता है, यहां तक कि खराब बुनियादी ढांचे के साथ। समानांतर अधिनियमों और बाजारों के सह–अस्तित्व के कारण राज्यों में बाजारों का ई–नाम में एकीकृत होना मुश्किल हो रहा है।
- *ई–नाम के नियमों और विनियमों के संबंध में राज्यों के मुद्दे* : राज्यों के बाजार नियम ई–नाम के नियमों और विनियमों से भिन्न हैं, इसलिए ई–नाम को स्वीकार करना राज्यों के लिए बहुत कठिन है।
- *बाजार प्रदर्शनकारियों की निम्न साक्षरता दर* : ई–नाम एक कंप्यूटर पोर्टल आधारित सेवा है, जिसे उपयोग और समझना हितधारकों के लिए कठिन है क्योंकि अधिकांश बाजार प्रदर्शनकारी अशिक्षित हैं।

राष्ट्रीय कृषि बाजार का गठन एक ऐतिहासिक पहल है। यह किसानों को अपने उत्पाद की बिक्री के अधिक विकल्प प्रदान करेगा और किसानों को गोदाम आधारित बिक्री के माध्यम से बाजार की पहुंच बढ़ाएगा, जिससे उत्पाद को मंडियों में ले जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। स्थानीय व्यापारियों के लिए, ई–नाम राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच का अवसर प्रदान करेगा, जबकि बड़े व्यापारियों के लिए यह स्थानीय मंडियों में सीधे भाग लेने का अवसर प्रदान करेगा और मध्यस्थता लागत को कम करेगा।

निष्कर्ष

ई–नाम भारतीय कृषि क्षेत्र में एक क्रांतिकारी पहल है, जो मौजूदा कृषि उपज विपणन समिति मंडियों और अन्य विपणन केंद्र को जोड़कर एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करता है। यह प्लेटफॉर्म किसानों को उनके उत्पादों के लिए अधिक विकल्प और बेहतर मूल्य प्रदान करने के साथ–साथ व्यापार प्रक्रिया को पारदर्शी और कुशल बनाता है। ई–नाम की मदद से किसान अपने उत्पादों की बोली लगवाने के लिए स्थानीय और राज्य स्तर से परे जाकर राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच सकते हैं। इसके अतिरिक्त, व्यापारियों और खरीदारों को भी अधिक व्यापक बाजार तक पहुंच मिलती है, जिससे मध्यस्थता लागत में कमी आती है और व्यापार की मात्रा में वृद्धि होती है।

हालांकि ई–नाम के कार्यान्वयन में कुछ चुनौतियाँ हैं, जैसे विभिन्न बाजारों में गुणवत्ता और मानकों में असमानता, मूल्य श्रृंखला का समन्वय और ग्रामीण बाजारों का एकाधिकार, लेकिन इसके लाभ बहुत महत्वपूर्ण हैं। ई–नाम का उद्देश्य एक समान, कुशल और लाभकारी कृषि विपणन प्रणाली का निर्माण करना है, जो अंततः किसानों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए अधिक लाभकारी सिद्ध हो।